

नव भारत



एक नजर में



प्रधानमंत्री मौजूदा सवालों का संसद में दें जवाब : विपक्ष

नयी दिल्ली, 22 जुलाई. इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज यहाँ संसद भवन परिसर में बैठक हुई जिसमें सभी दलों के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा सवालों का सदन में जवाब देना चाहिए. कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में इंडिया गठबंधन नेताओं की बैठक हुई जिसमें, ज्वलंत मुद्दों पर सवालों के जवाब देने के लिए श्री मोदी की सदन में उपस्थिति पर जोर देने का सामूहिक निर्णय लिया गया है.

वलर्क ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर ही लगाई फांसी

दुर्ग, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई कोर्ट परिसर में मंगलवार को एक वलर्क ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान सोमनाथ ठाकुर के रूप में हुई है. घटना की सूचना के बाद मौक पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई है. जानकारी के मुताबिक घटना का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को कुछ लोग कोर्ट रुम पहुंचे और देखा कि सोमनाथ फंदे से लटका हुआ है. तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

दुर्गई से आए कपल से 28 किलो गोल्ड पेस्ट जब्त

सुरत, गुजरात के सुरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अब तक की सबसे बड़ी सोने की तस्करी का पर्दाफाश किया है. तलाशी के दौरान कपल के शरीर के ऊपरी हिस्से, खासकर पेट के आसपास बेल्ट और कपड़ों में छुपाकर रखा गया करीब 28 किलो गोल्ड पेस्ट बरामद हुआ. महिला के पास से 16 किलो और पुरुष के पास से 12 किलो पेस्ट मिला, जिससे अनुमानित 20 किलो से अधिक शुद्ध सोना निकाला जा सकता है. इस बरामदगी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रुपये है.

धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार

हरिवंश चलाएंगे राज्यसभा की कार्यवाही, नीतीश हो सकते हैं उपराष्ट्रपति



भेजकर स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सकीय सलाह का हवाला देते हुए पद छोड़ने की घोषणा की.

मंगलवार दोपहर राष्ट्रपति ने धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया.

राज्यसभा में भी उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही शुरू की, लेकिन शून्यकाल के दौरान विपक्ष के विरोध के चलते उसे भी स्थगित कर देना पड़ा. उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही शुरू करते हुए सबसे पहले वार्ड एस आर कांग्रेस के निरंजन रेड्डी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत कार्यस्थान प्रस्ताव के 12 नोटिस मिले हैं.

हलचल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सोमवार रात अचानक इस्तीफे को लेकर रही. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र



धनखड़ की भूमिका सराहनीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है. मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ.

अब राज्यसभा की कार्यवाही उपसभापति हरिवंश चलाएंगे, जब तक कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 90 के तहत किसी अन्य सदस्य को अस्थायी सभापति नियुक्त नहीं करतीं. संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराना आवश्यक है. सूत्रों के अनुसार कुछ राजनीतिक सूत्र इस घटनाक्रम को बिहार विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं.

सियासी अटकलें और भोज की चर्चा

धनखड़ के इस्तीफे से ठीक पहले शनिवार को उन्होंने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर विशाल भोज का आयोजन किया था, जिसमें सभी प्रमुख दलों के सांसद, नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 800 से ज्यादा लोग शामिल हुए. इस भोज के दो दिन बाद इस्तीफा देना, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

इस्तीफे की संभावित वजह

हालांकि धनखड़ ने स्वास्थ्य को कारण बताया, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि उनका महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करना, सरकार की नाराजगी और वरिष्ठ मंत्रियों का उनके साथ बैठक में उपस्थित न होना संकेत देता है कि इस्तीफे के पीछे कोई गंभीर असहमति रही है. इससे पहले वे न्यायपालिका को लेकर भी कई बार मुखर रहे थे, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेएफ रद्द किए जाने पर.

संविधान और अगला कदम

धनखड़ का इस्तीफा अनुच्छेद 67(ए) के तहत स्वीकार किया गया है. अब सरकार को 6 महीने के भीतर उप-राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा. इस बीच, सत्र की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए उपसभापति हरिवंश के पास अधिकार रहेगा. इस तरह, संसद का मानसून सत्र हंगामे के साथ-साथ एक संविधानिक और राजनीतिक घटनाक्रम का गवाह बनता जा रहा है, जिसने संसद से सड़क तक बहस को तेज कर दिया है. हालांकि, अभी तक धनखड़ ने स्वयं इन अटकलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है. उनके इस्तीफे ने संसद के इस मानसून सत्र को नई राजनीतिक दिशा दे दी है और अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि सरकार अगला उपराष्ट्रपति कौन बनाएगी और विपक्ष इन घटनाओं को आगे किस तरह से उठाता है.

डाटा सटीक तो नीति भी होगी कारगर

राज्य सरकार की नीतियों का आधार बनेगा डाटा

कैबिनेट ने डी डाटा सुदृढीकरण योजना को मंजूरी दे दी है.



प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 22 जुलाई. कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश की डाटा सुदृढीकरण योजना को मंजूरी दे दी है.

निर्णय के तहत राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से सांख्यिकी से समृद्धि की दिशा में एक नई पहल कर रही है. योजना से सरकार को डाटा के आधार पर बेहतर और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी. साथ ही डाटा और उसका विश्लेषण समय पर मिलने से सरकार बेहतर नीति बना सकेगी. समस्त विभाग बिना किसी रुकावट के डाटा साझा कर सकेंगे, जिससे काम में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी. स्वतंत्र शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को भी डाटा उपलब्ध होगा, जिससे नई योजनाओं का निर्माण आसान होगा.

नागरिकों को भी डाटा की जानकारी मिल सकेगी, जिससे शासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा. डाटा की

कैबिनेट ने एम्पी पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के तहत संचालित (5x23) मेगावाट गांधीसागर एवं (4x43) मेगावाट) राणाप्रताप सागर जल विद्युत गृह के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए मप्र द्वारा देय राशि का अनुमोदन कर दिया है. निर्णय अनुसार गांधीसागर जल विद्युत गृह की पांचों इकाइयों (5x23 मेगावाट) के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण पर 464 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि खर्च की जायेगी. इसी तरह राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह की चारों इकाइयों (4x43 मेगावाट) के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण पर 573 करोड़ 76 लाख रुपये खर्च होंगे.

उपलब्धता से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

राष्ट्रपति मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस

राष्ट्रपति के शीर्ष अदालत से राय मांगने के मामले में केंद्र

नयी दिल्ली, 22 जुलाई. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर इस सवाल पर अपना पक्ष रखने को कहा है कि क्या अदालतें राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय-सीमा और प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकती हैं?

इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मई को शीर्ष अदालत से राय देने को कहा था और इसमें 14 प्रश्न उठाये थे. मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंद्रकर की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से राय मांगने के मामले



5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करने के साथ ही अर्दोनी जनरल आर वैकटरमानी से भी इस मामले में न्यायालय की सहायता करने को कहा. पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई तारीख तय की है. पीठ ने यह भी कहा कि अगस्त के मध्य से संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी. उच्चतम न्यायालय ने 8 अप्रैल को अपने एक फैसले में सभी राज्यपालों को विधानसभा से पारित विधेयक को मंजूरी देने की समयसीमा तय कर दी थी.

में सुनवाई की और विचार करने पर सहमति व्यक्त की.

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ कोचर दोषी

सुप्रीम एनर्जी के जरिए पति की कंपनी को मिला पैसा

नयी दिल्ली, 22 जुलाई. आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर को 2009 में वीडियोकॉन समूह को 300 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर करने के बदले 64 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का दोषी पाया गया है. यह निर्णय तत्करी और विदेशी मुद्रा हेराफेरी अधिनियम (एएमएफईएएमए) के अंतर्गत अपोलीय न्यायाधिकरण ने सुनाया है.

वक्फ विवाद पर दायर याचिका स्थानांतरित से इनकार

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती देने वाली रिट याचिका शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.



न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि चंदा कोचर द्वारा वीडियोकॉन समूह को ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया में हितों का गंभीर टकराव था. लोन स्वीकृति के कुछ ही समय बाद, वीडियोकॉन समूह की एक इकाई के जरिए 64 करोड़ रुपये की राशि उनके पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर रिन्यूबल्स प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित कर दी गई.

थाना परिसर में एएसआई ने लगाई फांसी

वीडियो बनाकर 2 टीआई पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

गोदान थाने के टीआई लाइन अटैच



दतिया, 22 जुलाई. थाना गोदान में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद पावन ने थाना परिसर स्थित सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उनका शव मंगलवार को फंदे पर लटका मिला है. आत्महत्या के पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है. प्रमोद ने वीडियो में टीआई अरविंद भदौरिया समेत 4 लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. प्रमोद के 3 वीडियो सामने आये हैं. तीनों में यही आरोप लगाये हैं. टीआई भदौरिया एवं एक अधक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है.

वीडियो में प्रमोद कह रहे हैं कि उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया. उन्हें पिछले 15 दिनों से थाने से बाहर नहीं जाने

डिप्टी कमिश्नर के घर ईओडब्ल्यू का छापा

जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के घर छापा मारा है. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर की गई है. शंकरशाह नगर स्थित सरवटे के निवास पर सुबह से ईओडब्ल्यू की टीम दरतावेजों की जांच कर रही है. अब तक की जांच में टीम को कई अहम दरतावेज और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े सुराग मिले हैं.



3 अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप आई भारत

- भारतीय वायु सेना को मिलेगी मजबूती
- 25 से अधिक देश करते हैं संचालन
- सेना में पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर
- दूसरा खेप नवंबर 2025 तक आने की उम्मीद

और सशक्त बनाएगा. शक्ति और चपलता के कारण, इसे हवा का टैंक भी कहा जाता है. इस दौरान भारतीय सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी. पोस्ट में लिखा भारतीय सेना ने अपाचे को शामिल किया. भारतीय सेना के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि सेना विमानन के लिए अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहली खेप मंगलवार को भारत पहुंच गया है. ये अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म इंडियनआर्मी की परिचालन क्षमताओं को काफी मजबूत करेंगे. गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों का संचालन कर रही है. अब सेना को भी इन्हें सौंपा गया है, जिससे जमीनी लड़ाइयों में अत्यधिक मारक और रात्रि अभियानों में तेजी से कार्रवाई संभव होगी.

MARUTI SUZUKI ARENA

पेश है **WAGONR WALTZ EDITION**

₹60,000* तक की एक्सेसरीज मुफ्त

6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड

इंफोटेनमेंट सिस्टम 15.74 से.मी. डिजाइनर सीट कवर रिवर्स पार्किंग कैमरा फॉग लैम्प और फॉग लैम्प गार्निश फ्रंट क्रैम ग्रिल

नजदीकी शोरूम के बारे में जानने के लिए स्कैन करें

आज ही ई-बुकिंग करें WWW.MARUTISUZUKI.COM

हमसे संपर्क करें **1800-102-1800**

*Offer includes consumer offer, retail support, exchange/ scrappage offer, and ISL/ Rural offer (wherever applicable) on select models/ Variants and in select states only. Terms and conditions apply. The terms and conditions are subject to change without any prior notice. Car models and accessories shown may vary from the actual product. Offers may vary from city to city and variant to variant for all models. Accessories and features shown in the pictures may not be a part of the standard fitment and may vary according to the variant. Creative visualization. Black glass on the vehicle is due to lighting effect. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes only. Offers valid till 31st July 2025 or till stocks last, whichever is earlier. 3 years or 100 000km whichever is earlier. Extendable upto 6 years or 1 60 000km whichever is earlier. Hill Hold Control Feature available in select variants only. ESP is a registered trademark of Mercedes-Benz Group AG.